

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 134 का उत्तर

आकांक्षी जिलों में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण

*134. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का निकट भविष्य में आकांक्षी जिलों में सभी रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का श्रावस्ती जिले सहित देश के सभी आकांक्षी जिलों में नए रेलपथ बिछाने/मौजूदा रेलपथों के दोहरीकरण और नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आकांक्षी जिलों में रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण/सुदृढीकरण के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री राम शिरोमणि वर्मा के तारांकित प्रश्न सं. 134 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, भारतीय रेल में इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 157 स्टेशन आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु आकांक्षी जिलों में स्थित चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

आकांक्षी जिलों में स्टेशनों की संख्या	आकांक्षी जिलों में स्टेशनों के नाम
157	<p> आबू रोड, अनुग्रह नारायण रोड, अराकू, अररिया कोर्ट, बहराईच, बलांगीर, बलरामपुर, बालसिरिंग, बांका, बनमनखी, बानो, बड़ागामदा जंक्शन, बारां, बरौनी, बरगावां, बरहनी, बरकाकाना, बारसोई जंक्शन, बासुकीनाथ, बेगुसराय, भद्राचलम रोड, भानुप्रतापपुर, भवानीपटना, बियावरा राजगढ़, बोकारो स्टील सिटी, चाईबासा, चक्रधरपुर, चंदौली मझवार, चंद्रपुरा, छबड़ा गुगोर, चित्रकुट धाम कर्वी, चोपन, कडप्पा, दाहोद, डाल्टनगंज, दमनजोड़ी, दमोह, डांगोपोसी, ढेंकनाल, ढोली, ढोलपुर, धुबरी, दुमका, फतेहपुर, फिरोजपुर कैंट, गंगाघाट, गंजबासौदा, गढ़वा रोड, गढ़वा टाउन, गौरीपुर, गया, घाटशिला, गिरिडीह, गोड्डा, गोविंदपुर रोड, गुना, गुनुपुर, गुरारू, हैदर नगर, हरिद्वार जंक्शन, हरिशंकर रोड, हरपालपुर, हटिया, हज़ारीबाग रोड, हिंडौन सिटी, जगदलपुर, जैसलमेर, जमुई, जनकपुर रोड, जपला, जयपुर, कांटाबांजी, करहागोला रोड, काशीपुर जंक्शन, कटिहार जंक्शन, केसिंगा, खगड़िया जंक्शन, खजुराहो जंक्शन, खंडवा, खरियार रोड, किच्छा, कोरापुट जंक्शन, कोरबा, लाभा, लखमीनिया, लातेहार, लिमखेड़ा, लोहरदगा, महासमुंद, महेशखूंट, मजबत, मानिकपुर जंक्शन, मनोहरपुर, मानसी जंक्शन, एमसीएस छतरपुर, मेरामंडली, मोगा, मोतीपुर, मुहम्मद गंज, मुनिगुड़ा, मुरी जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, नबीनगर रोड, नगर उंटारी, नामकोम, नंदुरबार, नवादा, ओरगा, उस्मानाबाद, पहाड़पुर, पाकुड़, परमाक्कुडी, पारसनाथ, पारलाखेमुंडी, पार्वतीपुरम, पाठशाला, पिंडवाड़ा, पिस्का, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रफीगंज, रायचूर जंक्शन, राजपलायम, राजमहल, राम दयालु नगर, रामनाथपुरम, रामदेवरा, रामेश्वरम, रामगढ़ कैंट, रांची जंक्शन, रायगढ़ा, रेनुकूट, रूड़की, रुथियाई, साहिबगंज, साहिबपुर कमाल, सलौना, सालमारी, श्री महावीरजी, सिद्धार्थनगर, सिल्ली, सिमुलतला, सिंगरौली, सीतामढी, सोनभद्र, श्रीविल्लिपुतूर, टांगला, टाटानगर, टाटीसिलवाई, टिटलागढ़ जंक्शन, तुलसीपुर, उदलगुरी, विदिशा, विरुधुनगर, व्यासनगर, वडसा, वाशिम, यादगीर </p>

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास एक जारी रहने वाली सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/विकास/पुनर्विकास के लिए कार्यों को मंजूरी देने और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार, क्योंकि रेलवे की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम छोर संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रॉफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 44,488 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) जिनकी लागत लगभग ₹7.44 लाख करोड़ है, योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक लगभग ₹2.92 लाख करोड़ का व्यय किया गया है। सारांश इस प्रकार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर)	मार्च 2024 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/मल्टी ट्रेकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

सभी रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

भारतीय रेल में नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	कमीशन किया गया नया रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 किलोमीटर	4.2 किलोमीटर प्रतिदिन
2014-24	31,180 किलोमीटर	8.54 किलोमीटर प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में आकांक्षी जिलों सहित भारतीय रेल में कुल 60,673 किलोमीटर लंबाई के 894 अदद सर्वेक्षण (287 नई लाइन, 14 आमामान परिवर्तन और 593 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, श्रावस्ती जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली ₹92,001 करोड़ की लागत वाली 5,874 किलोमीटर कुल लंबाई की 68 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 03 आमामान परिवर्तन और 49 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,313 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक ₹28,366 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर)	मार्च 2024 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	16	1740	297	8672
आमान परिवर्तन	3	261	0	26
दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग	49	3873	1016	19668
कुल	68	5874	1313	28366

नई लाइन परियोजना में भिनगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उत्तरौला, मेहदावल, बांसी के रास्ते बहराइच-खलीलाबाद (240 किलोमीटर) का कार्य शुरू कर दिया गया है।

वर्ष 2014 से, बजट आबंटन और परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले अवसंरचना एवं संरक्षा कार्यों के लिए वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	बजट परिव्यय	2009-14 के दौरान आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	₹1,109 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	-
2024-25	₹19,848 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	17 गुना से अधिक

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशनिंग	2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	199 किलोमीटर प्रतिवर्ष	-
2014-24	490 किलोमीटर प्रतिवर्ष	2 गुना से अधिक

2023-24 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 1,752 किलोमीटर (1328 किलोमीटर नई लाइन, 25 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 399 किलोमीटर दोहरीकरण) खंड कमीशन कर दिए गए हैं।
